

INDIAN

POLITY

BY – SUJEET BAJPAI SIR



- 3. Right
 against
 exploitation
 (Articles
 23–24)
- (a) Prohibition of traffic in human beings and forced labour (Article 23).
- (b) Prohibition of employment of children in factories, etc. (Article 24).



4. Right to freedom of religion (Article 25–28)

- (a) Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion (Article 25).
- (b) Freedom to manage religious affairs (Article 26).
- (c) Freedom from payment of taxes for promotion of any religion (Article 27).
- (d) Freedom from attending religious instruction or worship in certain educational institutions (Article 28).



- 5. Cultural and educational rights (Articles 29–30)
- (a) Protection of language, script and culture of minorities (Article 29).
- (b) Right of minorities to establish and administer educational institutions (Article 30).

S Simi

6. Right to Right to move the Supreme Court for the enforcement of constitutional fundamental rights including the writs of (i) habeas corpus, remedies (ii) mandamus. (iii) prohibition. (iv) certiorari, and (v) quo (Article 32)

Heart & Soul ob] Indian Consti

- 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- (a) बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)।
- (b) कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)।

- 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) (a) अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)।
 - (b) धार्मिक कार्यों के प्रंबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)।
 - (c) किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)।

(d) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।

 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

- (a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29)।
- (b) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)।
- 6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं-(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण,(ii) परमादेश,(iii) प्रतिषेध,(iv) उत्प्रेषण, (v) अधिकार पृच्छा (अनुच्छेद 32)।

WRIT

HABEAS CORPUS

MANDAMUS

PROHIBITION

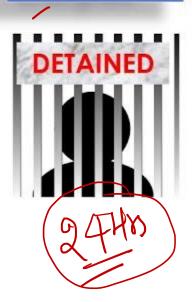
CERTIORARI

QUO-WARRANTO

5 To have the >We command We Coxfilt Authority
What Authority

INDIAN POLITY – (5) WRITS

Habeas Corpus



प्रमाद्श Mandamus

Supreme Court

Do your PUBLIC DUTY



3cgQq Certiorari

Superior Court

TRANSFER proceedings records

Check Judgement

Inferior Court / Quasi-Judicial Authority Prohibition

Superior Court



Inferior Court / Quasi-Judicial Authority Quo Warranto

Supreme Court





Right to Constitutional Remedies



Directive
Principles of
State Policy
[DPSP]



Part-4
Art-36-51,
Art-36-51,
Treland

Justiciable



Non-Tusticiable **Fundamental** Directive Rights **Principles**



The Directive Principles of State Policy are enumerated in Part IV of the Constitution from Articles 36 to 51.

The framers of the Constitution borrowed this idea from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution.



राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों की गणना संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की जाती है।

संविधान निर्माताओं ने इस विचार को १९३७ के आयरिश संविधान से उधार लिया था, जिसने इसे स्पेन के संविधान से कॉपी किया था।



Article No.	Subject Matter
36.	Definition of State
37.	Application of the principles contained in this part
38.	State to secure a social order for the promotion of welfare of the people
39.	Certain principles of policy to be followed by the State

Gandhian Ides



- 39A. Equal justice and free legal aid
- 40 Organisation of village panchayats
- Right to work, to education and to public assistance in certain cases
- Provision for just and humane conditions of work and maternity relief
- 43. Living wage, etc., for workers
- 43A. Participation of workers in management of industries
- 43B. Promotion of co-operative societies
- 44. Uniform civil code for the citizens



ZHEGICI



- Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections
- Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health
- 48. Organisation of agriculture and animal husbandry
- Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife
- Protection of monuments and places and objects of national importance
- 50. Separation of judiciary from executive
- 51. Promotion of international peace and security



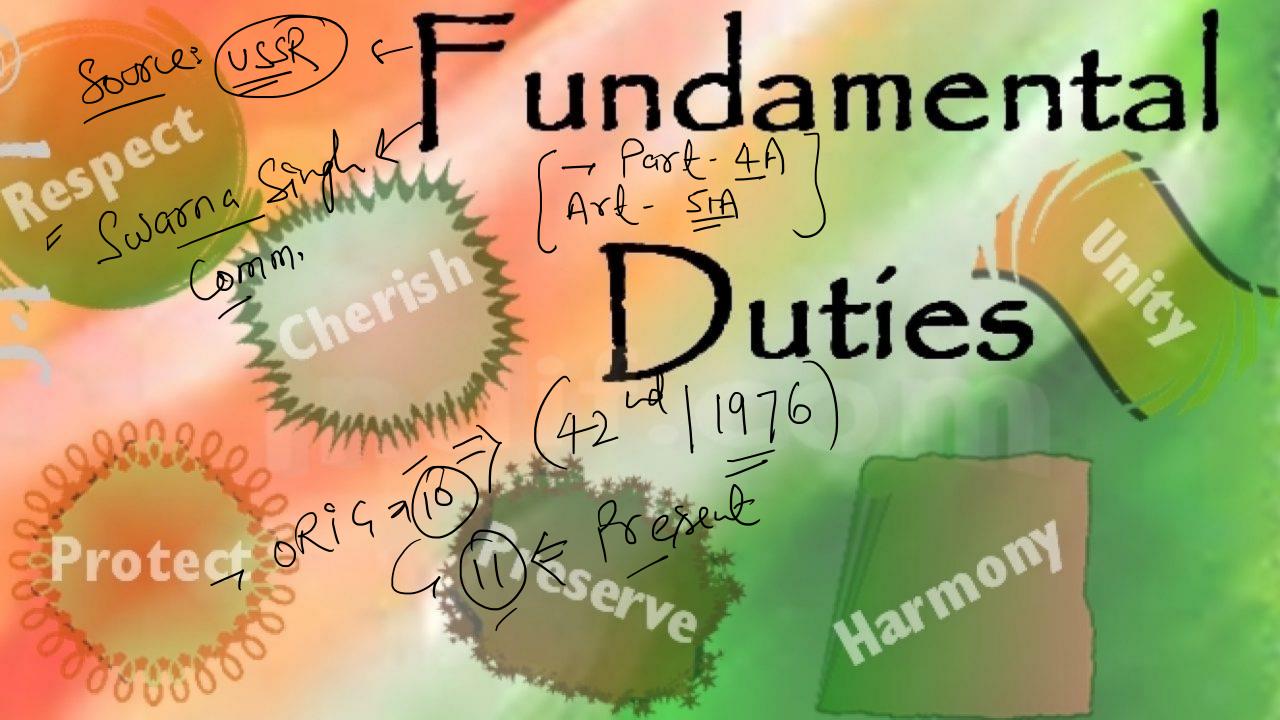
अनुच्छेद संख्या	विषय-वस्तु
36.	राज्य की परिभाषा
37.	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना।
38.	राज्य द्वारा जन-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना
39.	राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति–सिद्धांत
39.A	समान न्याय एवं नि:शुल्क कानूनी सहायता
40.	ग्राम पंचायतों का संगठन
41.	कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता



42.	न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान।
43.	कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि
43.A	उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता
43.B.	सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
44.	नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
45.	बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
46.	अनु. जाति, अनु. जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक, तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना



47.	पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन-स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने सम्बन्धी सरकार का कर्त्तव्य।
48.	कृषि एवं पशुपालन का संगठन
48.A	पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा
49.	स्मारकों, तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
50.	न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव
51.	अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन



FUNDAMENTAL DUTIES

- To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem
- To cherish and follow noble ideals, which inspired our national struggle for freedom
- To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India
- To defend the country and render national service when called upon to do so
- To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women
- To value and preserve the rich heritage of our composite culture

- To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures
- To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform
- To safeguard public property and to abjure violence
- To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement
- Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen

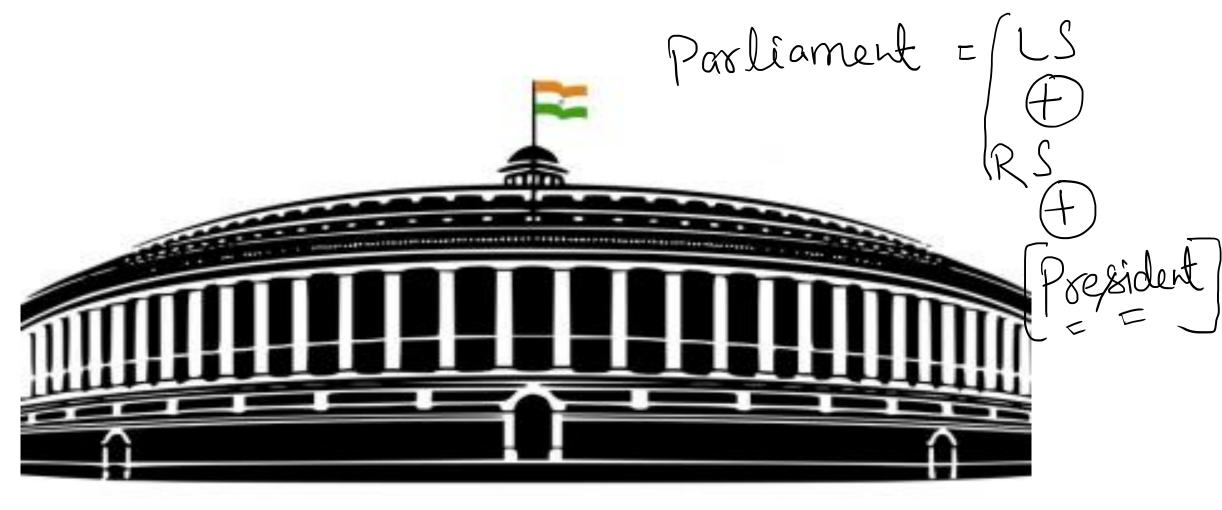




भारतीय संविधान

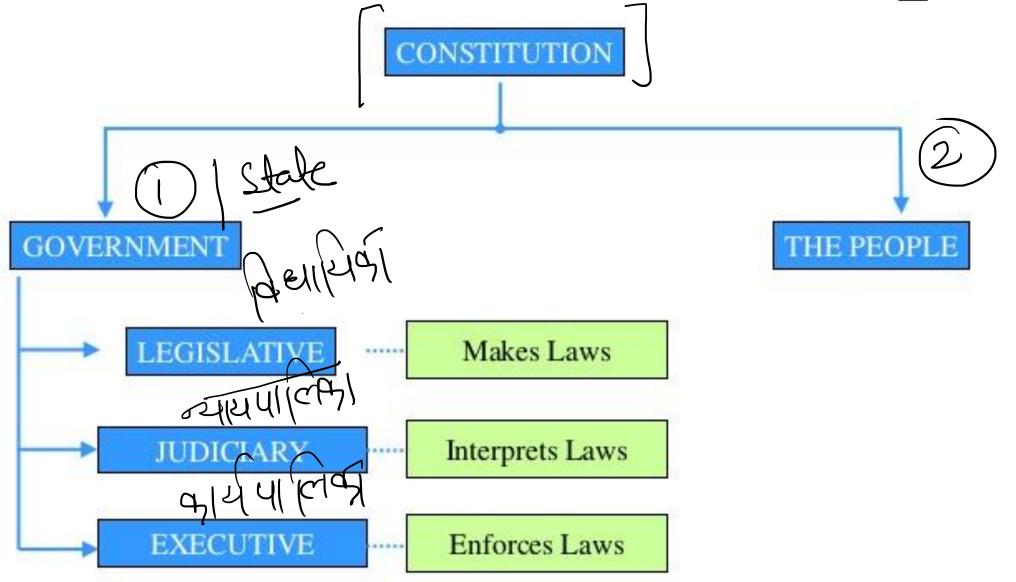
मौतिक कर्तव्य

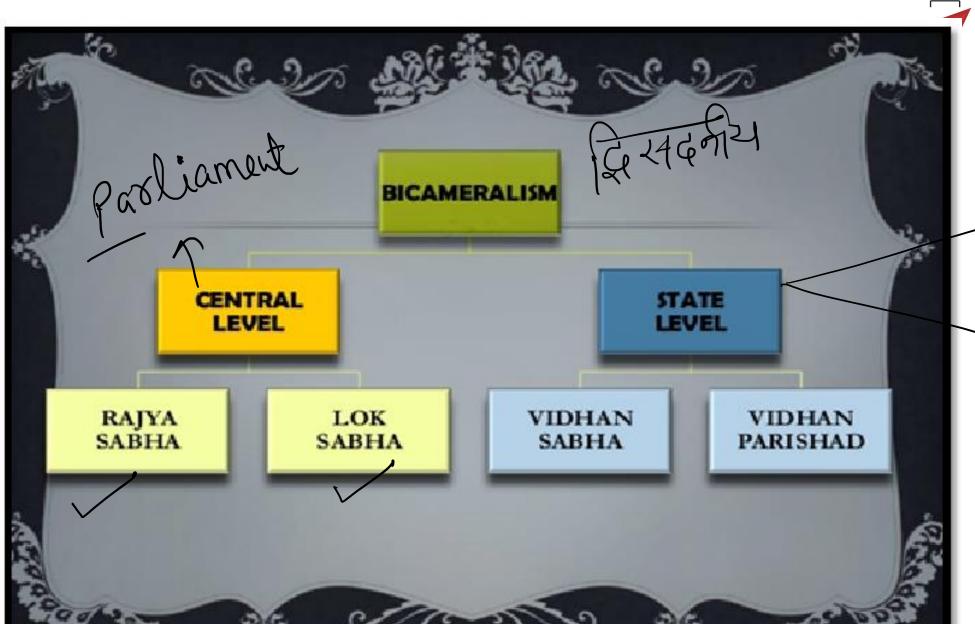
- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शी, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
- 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
- 4. देश की रक्षा करें।
- 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
- 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
- 7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
- 8. वैज्ञातिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
- 9. सार्वजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
- 10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
- 11. माता पिता या संरक्षक द्वारा ६ से १४ वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।



PARLIAMENT OF INDIA ·







SAFALTA CLASS™

An Initiative by **अमरउजाल**

uni cam,

BicAM.



The Parliament is the legislative organ of the Union government.

It occupies a pre-eminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government, also known as

'Westminster' model of government.

>> place in London



संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। यह सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में एक पूर्व-प्रख्यात और केंद्रीय पद पर है, जिसे सरकार के ' वेस्टमिंस्टर ' मॉडल के रूप में भी जाना जाता है।



Articles 79 to 122 in Part V of the Constitution deal with the organisation, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers and so on of the Parliament.

संविधान के भाग V में अनुच्छेद 79 से 122 संगठन, संरचना, अविध, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शिक्तियों आदि के साथ संसद के साथ व्यवहार करते हैं।



Under the Constitution, the Parliament of India consists of three parts viz, the President, the Council of States and the House of the People.

In 1954, the Hindi names 'Rajya Sabha' and 'Lok Sabha' were adopted by the Council of States and the House of People respectively.

संविधान के तहत भारत की संसद में तीन भाग होते हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्य परिषद और जनता का घर ।

1954 में राज्य परिषद और जन सभा द्वारा क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा नाम अपनाए गए।



The parliamentary form of government emphasises on the interdependence between the legislative and executive organs.

Hence, we have the 'President-in-Parliament' like the 'Crown-in-Parliament' in Britain.

सरकार का संसदीय रूप विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच परस्पर निर्भरता पर जोर देता है।

इसलिए, हमारे पास ब्रिटेन में क्राउन-इन-पार्लियामेंट की तरह 'राष्ट्रपति-इन-पार्लियामेंट 'है।



The presidential form of government, on the other hand, lays stress on the separation of legislative and executive organs.

Hence, the American president is not regarded as a constituent part of the Congress.

दूसरी ओर, सरकार का राष्ट्रपति रूप विधायी और कार्यकारी अंगों के अलग होने पर जोर देता है ।

इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का घटक हिस्सा नहीं माना जाता ।







Composition of Rajya Sabha

The maximum strength of the Rajya Sabha is fixed at 250, out of which, 238 are to be the representatives of the states and union territories (elected indirectly) and 12 are nominated by the president.

राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 तय है, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए) के प्रतिनिधि होने हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत हैं।



At present, the Rajya Sabha has 245 members. Of these, 229 members represent the states, 4 members represent the union territories and 12 members are nominated by the president.

The Fourth Schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories.



फिलहाल ग्रज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।



The president nominates 12 members to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in ART, LITERATURE, SCIENCE AND SOCIAL SERVICE.

राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं।

